

समिति फॉर डेमोक्रेसी

प्रलिस के लिये

समिति फॉर डेमोक्रेसी

मेन्स के लिये

लोकतंत्र: अर्थ और महत्त्व, चुनौतियाँ, भारत द्वारा इस संबंध में किये गए प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और नरिंकुशता का सामना करने के लिये' संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 'समिति फॉर डेमोक्रेसी' का आयोजन किया गया।

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'प्रेसडिंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल' की स्थापना संबंधी घोषणा की जो वदिशी सहायता पहल प्रदान करेगी।
- इस पहल को 424.4 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक पूँजी के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य 'मुक्त एवं स्वतंत्र मीडिया' का समर्थन करना, भ्रष्टाचार से लड़ना, लोकतांत्रिक सुधारों को मजबूत करना, लोकतंत्र के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग और स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बडि

■ परचिय

- इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि किस प्रकार स्वतंत्र और अधिकारों का सम्मान करने वाले समाज वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे कि [कोविड-19 महामारी](#), [जलवायु संकट](#) और [असमानता](#) से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये मलिकर काम कर सकते हैं।
- यह सम्मेलन तीन प्रमुख वषियों पर केंद्रित था:
 - सत्तावाद से बचाव
 - भ्रष्टाचार का संबोधन
 - मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना

■ भारत का पक्ष

- लोकतंत्रों को संयुक्त रूप से सोशल मीडिया और क्रिप्टो से संबंधित मुद्दों से निपटना चाहिये, ताकि उनका उपयोग कमजोर करने के बजाय लोकतंत्र को सशक्त बनाने हेतु किया जा सके।
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी 2,500 साल पुरानी लोकतांत्रिक परंपराएँ हैं और डिजिटल समाधानों के माध्यम से भारत लोकतांत्रिक अनुभव को साझा कर सकता है।
 - भारत में लच्छिवियों और अन्य लोगों के तहत प्राचीन शहर राज्यों में लोकतंत्र की सभ्यतागत परंपरा का उल्लेख मलिता है, जो वैदिक और बौद्ध काल के अंत में भारत में विकसित हुआ तथा प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक जारी रहा।
- लोकतंत्र ने दुनिया भर में वभिन्न रूप ले लिये हैं और ऐसे में लोकतांत्रिक प्रथाओं में कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने की आवश्यकता है।
- लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने और समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरमिा, उत्तरदायी शकियात नविरण तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र

■ अर्थ

- लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी नकियाय जैसे कि संसद बनाने के लिये आपस में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
- इसे 'बहुमत का शासन' भी कहा जाता है। इसमें सत्ता वरिसत में नहीं मलिती। जनता अपना नेता स्वयं चुनती है।

- प्रतनिधि चुनाव में हसिसा लेते हैं और नागरकि अपने प्रतनिधिको वोट देते हैं । सबसे अधकि मतों वाले प्रतनिधिको शक्ति प्राप्त होती है ।

■ संक्षपित इतहास

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है । भारत वर्ष 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रकि राष्ट्र बन गया । इसके बाद भारत के नागरकिों को वोट देने और अपने नेताओं को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ ।



MAPPED

THE 25 OLDEST DEMOCRACIES IN THE WORLD



Note: This infographic uses data from Bok, Miller and Rosato's "Comparative Political Studies" which goes back to the year 1800 and uses 219 countries.

They define a country as democratic if they meet the following conditions:



The executive is directly or indirectly elected in popular elections and is responsible either directly to voters or to a legislature.

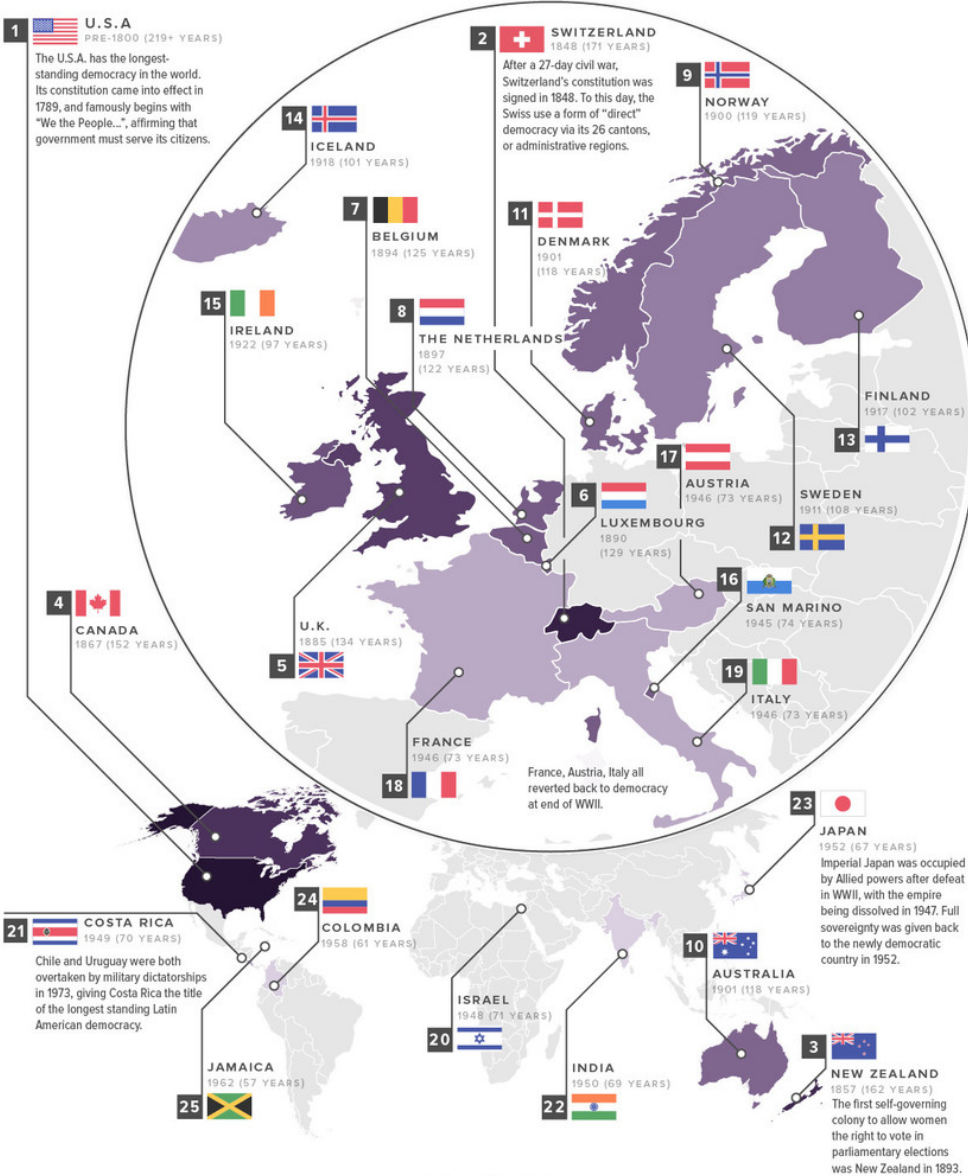


The legislature (or the executive if elected directly) is chosen in free and fair elections.



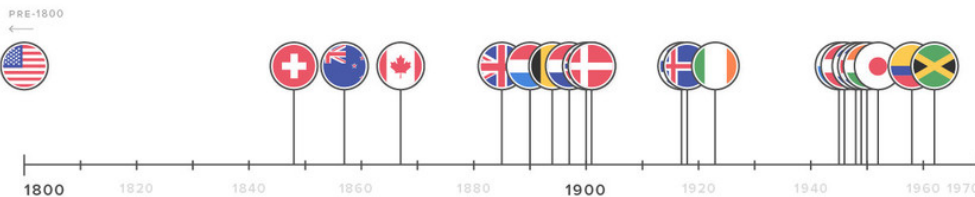
A majority of adult men has the right to vote.

Universal suffrage came later. In the U.S., for example, all women could not vote until 1920.



TIMELINE VIEW

In the grand scheme of human history, democracy is still a relatively new concept. In fact, the vast majority of the world's current democratic regimes are less than 50 years old.



■ लोकतंत्र को मज़बूत करने में भारत की भूमिका:

○ दुनिया भर में:

● कृषमता नरिमाण

- स्वतंत्र और नषिपकष चुनाव कराने में **चुनाव आयोग** के उल्लेखनीय रकिॉर्ड के अलावा, भारत ने कई दशकों तक एशिया, अफरीका और दुनिया के अन्य कषेत्रों के हज़ारों चुनावी अधिकारियों को चुनाव प्रबंधन तथा संसदीय मामलों में प्रशकिषण दिया है।

● वकिसातमक भागीदारी प्रशासन (DPA):

- भारत ने भौगोलिक कषेत्रों में कई वकिसाशील और नए लोकतंत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण वकिसा सहायता परयोजनाओं की पेशकश करने के लिये वदिश मंत्रालय (MEA) के भीतर एक 'वकिसातमक भागीदारी प्रशासन' (DPA) का नरिमाण किया है।
- इसमें अफगान संसद का नरिमाण और म्याँमार को अपनी प्रशासनिक एवं न्यायिक कषमताओं के उन्नयन के लिये सहायता प्रदान करना शामिल है।

● लोकतंत्र की नगिरानी के लिये अनुदान:

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का समर्थन करने हेतु 'संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी फंड' (UNDEP) और 'कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसी' के नरिमाण में भारत ने अमेरिका के साथ मलिकर महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई थी।
- संयोग से, भारत UNDEF के सबसे बड़े योगदानकर्त्ताओं में से एक है, जो दक्षिण एशिया में 66 गैर-सरकारी संगठनों के नेतृत्व वाली परयोजनाओं का समर्थन करता है।

● संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कॉकस:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी कॉकस बनाने में भी मदद की, जो कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर साझा मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक राज्यों को बुलाने वाला एकमात्र नकियाय है।

○ भारत में:

● नसलीय भेदभाव को समाप्त करना:

- भारत में एक दलित महिला को उच्च पद (मुख्यमंत्री के रूप में) तक पहुँचने के लिये प्रतनिधित्व दिया गया।

● सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

- इस अधिनियम ने पूरी तरह से नागरिक समाज संचालित जमीनी आंदोलन को आम नागरिकों के लिये सूचना को सही मायने में लोकतांत्रिक बना दिया है।

● लोकतांत्रिक वकिेंद्रीकरण:

- वर्ष 1992 में दो संवैधानिक संशोधन (73वें और 74वें) द्वारा जसि त्र-स्तरीय प्रशासन (ग्रामीण और शहरी स्थानीय नकियाय) की स्थापना की गई उसने पछिले तीन दशकों में गहरा प्रभाव स्थापित किया है।
- 30 लाख प्रतनिधियों के साथ वभिन्न स्तरों (**ग्राम सभा, पंचायत समिति जिला परिषद**) पर, यह अब तक वशि्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है।

■ लोकतंत्र से संबंधित चिंताएँ:

○ वैश्विक:

● राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में गरिावट:

- दुनिया भर के लोकतंत्र नए स्थापित - कई प्रमुख मापदंडों पर गंभीर संकटों से जूझ रहे हैं।
- लोकतंत्र की नगिरानी करने वाली संस्थाओं की रपिॉर्टों के अनुसार, लोकतंत्र में खतरनाक गरिावट देखी जा रही है।
- **डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020** के अनुसार, वशि्व की बहुत कम 9% आबादी 'पूर्ण' लोकतंत्र में रहती है।
 - म्याँमार, ट्यूनीशिया और सूडान में हालिया सैन्य तख्तापलट लोकतंत्र वशिधी ताकतों के नरितर उदय का प्रमाण है तथा इसकी बारंबारता वैश्विक लोकतंत्र समर्थकों की सामूहिक वफिलता को दिखाती है।

● बढ़ती सत्तावादिता:

- सत्तावादी शक्तियों, वशिषकर चीन के नरितर उदय से उत्पन्न बढ़ता खतरा एक प्रमुख चिंता का वषिय है।
- ऐसे समय में जब पश्चिम, वशिष रूप से अमेरिका और समृद्ध यूरोपीय देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतनि अपनी वैश्विक प्रतनिबद्धता को काफी हद तक समाप्त कर दिया है, चीन ने वैश्विक मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मानदंडों को फरि से परभाषित करने पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं।

○ उदाहरण:

- चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया है, वविादित **दक्षिण चीन सागर** में अपने कषेत्रीय दावों को मजबूर किया है, लाखों **उइगर मुसलमानों** को नजरबंदी शविरीं में डाल दिया है, **हॉन्गकॉन्ग** में राजनीतिक स्वतंत्रता को नयितरत किया है और कई भौगोलिक कषेत्रों में अपने प्रभाव को मज़बूत करने के लिये अभियान शुरू किया है।

○ भारत:

- **फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' रपिॉर्ट** में भारत की स्थिति को 'स्वतंत्र' से 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया है। वी-डेम रपिॉर्ट ने इसे एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए "चुनावी नरिंकुशता" करार दिया है।
- **ग्लोबल सटेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021** की रपिॉर्ट के अनुसार, "बैकस्लाइडिंग के कुछ सबसे चिंताजनक उदाहरणों" के साथ भारत 10 सबसे पीछे खसिकने वाले लोकतंत्रों में से एक था।

आगे की राह

- संवैधानिक लोकतंत्र के संस्थागतकरण ने भारत के लोगों को लोकतंत्र के महत्त्व को समझने और उनमें लोकतांत्रिक संवेदनाओं को वकिसति करने में

मदद की है।

- साथ ही, यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकार के सभी अंग देश के लोगों के विश्वास को बनाए रखने हेतु सद्भाव से कार्य करें और वास्तविक लोकतंत्र के उद्देश्यों को सुनिश्चित करें।
- सरकार को आलोचना को सरि से खारजि करने के बजाय सुनना चाहिये। लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने के सुझावों पर एक वचिरशील और सममानजनक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- प्रेस और न्यायपालिका, जिन्हें भारत के लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, को कार्यपालिका के कार्यों की ऑडिटिंग को सक्षम करने हेतु किसी भी कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/first-democracy-summit>

